

विचार बिन्दु

मनुष्य का कर्त्तव्य है कि वह उदार बनने से पहले त्यागी बने। –डिक्सन

ऐसी शिक्षा किस काम की?

शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यह है कि वह जीविकोपार्जन के साधन जुटाने में सहायक हो, एक अच्छा नागरिक बनाए, एक तर्कशील, विवेकशील व्यक्ति का निर्माण करे और जो वैज्ञानिक सोच रखता हो। इस आलेख में यह विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे कि हमारी शिक्षा व्यवस्था इन कसौटियों पर कितनी खरी उतरी है?

भारत की पहली शिक्षा नीति 1966 में, दूसरी 1986 में (जिसे 1992 में संशोधित किया गया) और हाल ही में 2020 में नई शिक्षा नीति घोषित की गई। सभी नीतियों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सबका उद्देश्य तो बहुत अच्छा था कि देश के सभी नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और वह ऐसे नागरिक तैयार करें जिनमें वैज्ञानिक सोच हो एवं दक्ष नागरिक बनाएं एवं जो अपने जीवन यापन के पर्याप्त साधन जुटा सकें। साथ ही वे विभिन्न प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए सदैव उत्सुक रहें।

सबसे पहले हम राजस्थान के संदर्भ में प्रारंभिक शिक्षा की ही बात करें। बालक बालिकाओं को अपनी स्थानीय बोली में पढ़ाने के बजाय उन्हें हिंदी की पुस्तकों से पढ़ाया जाता है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं, जो एक दूसरे से बहुत भिन्न हैं। अनेक शब्द और व्याकरण भी अलग हैं। इस कारण छोटे बच्चों, विशेषकर ग्रामीण, को हिंदी में लिखी हुई पुस्तकें बिल्कुल समझ में नहीं आती हैं। साथ ही पुस्तकों में काम लिए गए विभिन्न सन्दर्भों से भी उनका कोई जुड़ाव नहीं होता। इस कारण अनेक बच्चे प्रारंभिक कक्षाओं में ही शिक्षा चक्र से दूर हो जाते हैं। जो बच्चे औपचारिक विद्यालय में अनेक सामाजिक और आर्थिक कारणों से नहीं जा पाते, वे तो वैसे ही शिक्षा प्रणाली से बाहर हैं। उनके लिए अनौपचारिक शिक्षण की जो व्यवस्था थी, उसे भी सरकार ने 'शिक्षा का अधिकार कानून' के नाम पर बंद कर दी है। अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय खोलने के सरकारी निर्णय ने तो कोढ़ में खंज का काम किया है। विभिन्न जटिलताओं के चलते स्वैच्छिक संस्थाओं के लिए प्राथमिक विद्यालय को मान्यता प्राप्त करना वैसे ही संभव नहीं है।

स्कूली शिक्षा पद्धति में सबसे बड़ी खामी तो परीक्षा प्रणाली है जो केवल रटने पर आधारित है। समझ कर पढ़ने का कोई महत्व नहीं है। पुस्तकों के अध्याय भी उनके संदर्भ से एकदम कटे हुए हैं। कई बार तो विदेशी संदर्भों का उपयोग किया गया है। पूरी मूल्यांकन प्रणाली कुंजियों से उत्तर रटने पर निर्भर हो गई है। यही कारण है कि बोर्ड का 'पास' प्रतिशत इस बार 97–98–99% तक रहा है। अनेक विद्यार्थियों के 95%से अधिक अंक आए हैं। परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए केवल रटना होता है। जो विद्यार्थी परीक्षा के तीन घंटे में रटा हुआ उत्तर सही उाल दे, वह लगभग पूरे अंक ले आता है। किसी विषय के बारे में समझ को जांचने का तो कोई प्रयास ही नहीं होता है। 90% प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों से उन्हीं के पाठ्यक्रम से संबंधित सरल प्रश्न भी यदि अलग तरह से पूछ लें, तो अधिकांश उन्हें हल नहीं कर पाते हैं। विभिन्न प्रवेश और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग संस्थान इसीलिए खूब फलफूल रहे हैं और अभिभावक उनके आर्थिक शोषण का शिकार हो रहे हैं।

नौकरी प्राप्त करने के लिए भी वर्तमान परीक्षा पद्धति कुछ काम की नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि कोई राजकीय विद्यालय में शिक्षक बनना चाहे तो पहले उसे स्नातक के बाद बी. एड में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा देनी होती है। इसके लिए कोचिंग संस्थान हैं जो हजारों रुपए लेते हैं। इसमें उत्तीर्ण होने पर उसे दो वर्ष बी. एड की पढाई करनी होती है। इसकी फीस हजारों में हैं। इसके बाद उसे रीज (Rajasthan Eligibility Examination for teachers) की प्रतियोगी परीक्षा में बैठना होता है, जिसके लिए फिर कोचिंग करनी पड़ती है। इसमें सफल होने पर उसे फिर, रिक्रियंग निकलने पर एक और चयन परीक्षा में बैठने होता है। इसके परिणाम के आधार पर मेरिट के अनुसार चयन होने पर शिक्षा विभाग द्वारा नियुक्ति दी जाती है। जब विद्यार्थियों का मूल्यांकन परीक्षा में आए हुए अंकों के आधार पर नहीं हो होगा तो शिक्षकों का भी पूरा ध्यान केवल इसी पर रहता है कि कैसे प्रश्नों के उत्तर रटा दिए जाएं ताकि वह परीक्षा में अधिक अंक हासिल कर सके। यह दोष पूर्ण शिक्षा व्यवस्था का ही परिणाम है कि बहुत अच्छे अंकों से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठते हैं तो वह बहुत अच्छा नहीं कर पाते।

जहां तक शिक्षकों के पद पर नियुक्ति का प्रश्न है, युवा पीढ़ी के इतने वर्ष बर्बाद करने के बजाय, क्या यह अच्छा नहीं होता कि उन्हें स्नातक के परिणाम के आधार पर नौकरी पर रख लिया जाता? तत्पश्चात उन्हें नौकरी पर रहते हुए नियमित प्रशिक्षित किया जाता। इस प्रकार उन्हें अच्छा शिक्षक बनाया जा सकता है। इस प्रकार का अल्पकालिक प्रशिक्षण साल में दो तीन बार किया जा सकता है। इसके लिए आवश्यकता केवल इसी बात की है कि वर्तमान में जो पढाई और मूल्यांकन की व्यवस्था स्नातक और 12 वीं तक की है, उसे वैसे ही बना दिया जाए जिस प्रकार से चयन परीक्षा ली जाती है। इससे लाखों युवाओं के अत्यंत महत्वपूर्ण कई वर्ष बर्बाद होने से बच पाएंगे। ऐसा करके हम, उन लोगों के द्वारा बी.एड और एस.टी.सी पर व्यर्थ हुए समय और धन को बचा पाएंगे जो अंततः शिक्षक नहीं बनकर किसी और व्यवसाय में लग जाते हैं। इस प्रकार के प्रयोग सफलता पूर्वक अन्य देशों में किए गए हैं।

हमारे यहां पर महाविद्यालय और विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली उच्च शिक्षा की स्थिति भी कोई बेहतर नहीं है। सरकारी, सस्ती लोकायता हासिल करने के उद्देश्य से, प्रतिवर्ष कई नए महाविद्यालय और विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा कर देती है, किंतु पर्याप्त और उपयुक्त शिक्षकों के अभाव में यहां पढाई मात्र की भी नहीं हो पाती। वैसे भी शिक्षकों के अभाव में किस प्रकार की पढाई हो सकती है, यह कल्पना ही की जा सकती है। राजस्थान में तीन दशक पूर्व जब कि केवल तीन विश्वविद्यालय थे, अब उनकी संख्या बढ़कर लगभग 100 हो गई है। कई निजी विश्विद्यालय तो युवाओं के आर्थिक और मानसिक शोषण का माध्यम बन कर रहे गए हैं। यहां तो पैसे लेकर डिग्री बेचने तक का काम होता है।

कुल मिलाकर हम यही कह सकते हैं कि वर्तमान शिक्षा पद्धति ना तो देश के किसी काम की है न विद्यार्थियों के। देश में एम एस स्वामीनाथन के नेतृत्व में हरित क्रांति और कुरियन के नेतृत्व में श्वेत क्रांति हुई, जिसके सकारात्मक परिणाम निकले। अब देश प्रतीक्षा कर रहा है, शिक्षा क्रांति की। इस क्रांति के बाद ही भारत के विकास में, शिक्षा अपनी अपेक्षित भूमिका निभा सकेगी।

नहीं है। क्या इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था उन अभिभावकों के साथ विश्वास घात नहीं है जो बड़ी उम्मीद के साथ अपने बच्चों को कर्जा लेकर निजी विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए भेजते हैं? उच्च शिक्षा का तो यह हाल हो गया है कि कुछ वर्षों पूर्व, उत्तर प्रदेश में चरपासी के कुछ पदों पर नियुक्ति के लिए लाखों लोगों ने आवेदन किया, जिनमें से कई तो पीएचडी और इंजीनियरिंग स्नातक तक भी थे।

इस विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारी प्रारंभिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा कर देती है, किंतु पर्याप्त और उपयुक्त शिक्षकों के अभाव में यहां पढाई मात्र की भी नहीं हो पाती। वैसे भी शिक्षकों के अभाव में किस प्रकार की पढाई हो सकती है, यह कल्पना ही की जा सकती है। राजस्थान में तीन दशक पूर्व जब कि केवल तीन विश्वविद्यालय थे, अब उनकी संख्या बढ़कर लगभग 100 हो गई है। कई निजी विश्विद्यालय तो युवाओं के आर्थिक और मानसिक शोषण का माध्यम बन कर रहे गए हैं। यहां तो पैसे लेकर डिग्री बेचने तक का काम होता है।

तकनीकी और मेडिकल के पाठ्यक्रमों की स्थिति और भी अधिक खराब है। जो इन पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है वह बाद में उनके जीवन में व्यवसाय को चलाने के लिए कतई उपयोगी नहीं होता। मुख्े प्रबंध निदेशक, रीको के रूप में कार्य करते हुए कई बड़े उद्यमियों द्वारा यह शिकायत की जाती थी कि इंजीनियरिंग स्नातकों में से 20 से 25% भी उनके यहां पर किसी काम को करने में सक्षम नहीं हैं।

कहा जाता है कि निजी मेडिकल महाविद्यालय/विश्वविद्यालय से निकले विद्यार्थी अपना अस्पताल भले ही खोल लें, किंतु अस्पताल में इलाज करने की क्षमता उनमें विकसित नहीं हो पाती। शायद करोड़ों रुपए खर्च करके वे मेडिकल की पढाई ही अस्पतालों के मालिक बनने के लिए ही करते हैं ताकि व्यय किया गया पैसा शीघ्र वापस लू सकें।

यह तो हुआ शिक्षा का एक पहलु, जिसके बाद उपयुक्त रोजगार भी नहीं मिल पा रहा है। अब यदि हम उनके अच्छे इसान के रूप में और अच्छे नागरिक के रूप में विकसित होने की बात करें, तो इस दिशा में हमारी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था और भी असफल रही है। किसी भी अच्छी शिक्षा व्यवस्था से निकलने वाले व्यक्ति से यह अपेक्षा होती है कि वह सामाजिक सौहार्द को बढ़ाने वाला, संवैधानिक मूल्यों में विश्वास रखने वाला, जेंडर संवेदनशील और वैज्ञानिक सोच वाला होगा। क्या हम आज की युवा पीढ़ी में इन गुणों का समावेश देखते हैं? इसका उत्तर स्पष्ट रूप से 'नहीं' है। हम देखते हैं कि आजकल के युवा अनेक समाज और राष्ट्र विरोधी आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त हो कर रह गए हैं। इन्हें विभिन्न प्रकार के कट्टर धार्मिक संगठन अपने-अपने स्थायी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, उन्माद फैलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यह इसीलिए संभव हो पाता है कि युवाओं में वैज्ञानिक सोच विकसित करने का कोई व्यवस्थित प्रयास महाविद्यालयों में नहीं किया जाता। लगता तो ऐसा है कि, समय निकलने के साथ-साथ, अंधविश्वास, पूर्व की तुलना में कहीं अधिक बढ़ता जा रहा है। यदि शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी अधिकांश युवा तर्क हीन, विवेकशून्य और अंधविश्वासी हों, तो ऐसी शिक्षा वास्तव में न देश के लिए उपयोगी है, न उस व्यक्ति के लिए जो ऐसी शिक्षा प्राप्त कर रहा है। इसमें दोष छात्रों का नहीं माना जा सकता। जिन व्यक्तियों के हाथ में शिक्षा का संचालन है, चाहे वे शिक्षाविद हों, शिक्षा प्रशासक हों अथवा जनप्रतिनिधि, सबका यह दायित्व है कि वे हमारी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर गंभीरतापूर्वक विचार करें और उसे आज के समय की आवश्यकता के अनुसार लगातार बदलाव के लिए सक्षम बनाएं। यह उल्लेखनीय है कि जिस गति से आजकल विभिन्न तकनीकों में और विभिन्न क्षेत्रों में बदलाव हो रहा है, उतना शायद पहले कभी नहीं था। वही शिक्षा उपयोगी हो सकती है जो समय के साथ-साथ स्वयं बदलने के लिए विद्यार्थियों को समर्थ बनाए।

अधिक उपयोगी और उपयुक्त शिक्षा व्यवस्था तो वही होगी जहां शिक्षार्थी अनुभवजन्य ज्ञान प्राप्त करें। केवल जानकारी को रटने के आधार पर परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करना, किसी भी दृष्टि से उपयोगी सिद्ध नहीं होगा। सभी विद्यार्थियों का परीक्षाओं में पास होना किसी भी संस्था की गुणवत्ता का आकलन करने का पैमाना नहीं हो सकता। बोर्ड की परीक्षाओं में आधे से अधिक अंक तो प्रैक्टिकल और आंतरिक मूल्यांकन के हो जाते हैं, जिनमें लगभग सभी को शत प्रतिशत अंक मिलते हैं। इसके बाद मुख्य परीक्षा में यदि 10–20% भी अंक मिल जाएं तो वह छात्र उत्तीर्ण घोषित हो जाता है।

यदि 2047 तक विकसित भारत की कल्पना की जा सकारा किता है तो अभी से हमें वर्तमान शिक्षा प्रणाली, विशेषकर मूल्यांकन की व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन करना होगा। जहां तक केवल जानकारी हासिल करने का प्रश्न है, वह तो इंटरनेट के युग में कोई भी व्यक्ति किसी भी समय गुगल के माध्यम से कुछ सेकंड में प्राप्त कर सकता है। यह हमारी शिक्षा प्रणाली का दोष ही माना जा सकता है कि जिन भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिला है, उनमें से अधिकांश ऐसे थे जिन्होंने विदेशों में रहकर उच्च अध्ययन किया।

नई शिक्षा नीति में विषयों के चयन में लचीलापन लाने की बात कही गई है। साथ ही विद्यार्थी पूरे कोर्स में किसी समय प्रवेश लेकर छोड़ सकेगा। प्रश्न यही है कि क्या इसके लिए आवश्यक संख्या में उपयुक्त शिक्षक रखने हेतु पर्याप्त खर्च बढ़ाया जाएगा?

कुल मिलाकर हम यही कह सकते हैं कि वर्तमान शिक्षा पद्धति ना तो देश के किसी काम की है न विद्यार्थियों के। देश में एम एस स्वामीनाथन के नेतृत्व में हरित क्रांति और कुरियन के नेतृत्व में श्वेत क्रांति हुई, जिसके सकारात्मक परिणाम निकले। अब देश प्रतीक्षा कर रहा है, शिक्षा क्रांति की। इस क्रांति के बाद ही भारत के विकास में, शिक्षा अपनी अपेक्षित भूमिका निभा सकेगी।

—**अतिथि सम्पादक,**

राजेन्द्र भागवत

(पूर्व आई.ए.एस. अतिथी)



रामनिवास बैरवा

इस्लाम को मानने वाली पुरुष जाति अपने लिए तो आधुनिकता और आधुनिक जीवन शैली चाहते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए शरियत को कठोरता से लागू करना जरूरी मानती है। इसीलिए जिन भी इस्लामिक देशों ने आधुनिक पूंजीवादी या समाजवादी जीवनशैली में महिलाओं को भी बराबर का भागीदार बनाया उन देशों के उदार शासकों को अमरीका जैसे पूंजीवादी साम्राज्यवादी देशों ने समानान्तर इस्लाम को कट्टरता से मानने वालों को उभारा और इस्लामी दुनिया को शरियत के दायरे में बांधे रखना चाहा, जैसे ईराक, ईरान, मिश्र, तुर्की आदि। तेल सम्पन मध्य पूर्व के देशों को इस्लामिक कट्टरता से बांधे रखा है। अन्य विकसित और विकासशील देशों को जहां इस्लाम को मानने वालों की जनसंख्या ज्यादा है, उन्हें आधुनिक औद्योगिक विकास के रास्ते से भटकाने के उद्देश्य से उन देशों में अस्थिरता बनाये रखना पूंजीवादी साम्राज्यवादी देशों, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमरीका का मुख्य लक्ष्य रहा है। नव-स्वतंत्र अविकसित और विकासशील देशों में अस्थिरता बनाये रखना और उन्हें आंतरिक संघर्षों या पड़ौसी देशों के साथ युद्धरत रखना भी एक उद्देश्य रहा है। इस प्रकार कट्टर इस्लामिक लोगों के द्वारा विभिन्न विकसित और विकासशील देशों में अपनी गतिविधियां करने से और कुछ हासिल हो या न हो, उा धार्मिक दक्षिणपंथी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने में सफल रहे हैं और उन देशों में उग्र-दक्षिणपंथी धार्मिक राष्ट्रवाद को सामने आने का मौका दिया गया। इसी का परिणाम है कि पिछले दो दशकों में कई देशों में, इटली, जर्मनी,

एक करोड़ की लागत से बने साइकिल ट्रैक की चार साल में हालत खस्ता

ट्रैक की चार साल में हालत खस्ता

ट्रैक की चार साल में हालत खस्ता

पॉलिटेक्निक कॉलेज के चारों ओर बने ट्रैक की हालत ऐसी हो गई है कि साइकिलस्ट अब यहां साइकिल चलाने से भी कतराने लगे हैं

बीकानेर, (नर्स)। साइकिल प्रेमियों के लिए चार साल पहले जिस उम्मीद के साथ पॉलिटेक्निक कॉलेज के चारों ओर नगर निकास न्यास ने साइकिल ट्रैक बनवाया था, वह अब पूरी तरह जमींदोड़ होता नजर आ रहा है।

जानकारी के अनुसार लगभग एक करोड़ रुपए की लागत से बने इस ट्रैक की हालत ऐसी हो गई है कि साइकिलस्ट अब यहां साइकिल चलाने से भी कतराने लगे हैं। खंभे, अतिक्रमण और टूटे अवरोधक इसके दुर्घटना का न्यौता बना चुके हैं। करीब 4 साल पहले बीकानेर के तत्कालीन जिला कलेक्टर नमित मेहता की पहल पर नगर निकास न्यास ने लगभग एक करोड़ रुपए खर्च कर इस साइकिल ट्रैक का निर्माण कराया था। ट्रैक सार्दूल रोड, नई शिवबाड़ी रोड, वर्धमान हॉस्पिटल रोड, नई शिवबाड़ी रोड, वर्धमान हॉस्पिटल के सामने होते हुए व्यास

- करीब चार साल पहले बीकानेर के तत्कालीन जिला कलेक्टर नमित मेहता की पहल पर नगर निकास न्यास ने लगभग एक करोड़ रुपए खर्च कर इस साइकिल ट्रैक का निर्माण कराया था**
- ट्रैक सार्दूलगंज सर्किल से शुरू होकर पॉलिटेक्िक रोड, नई शिवबाड़ी रोड, वर्धमान हॉस्पिटल के सामने होते हुए व्यास कॉलानी के एंट्री पॉइंट तक जाता है**

कॉलोनी के एंट्री पॉइंट तक जाता है और महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज के हॉस्टल के पास से होते हुए वापस सार्दुल गंज सर्किल पर आकर समाप्त होता है। शिवबाड़ी रोड पर साइकिल ट्रैक के पास बने अवरोधक कई जगह से टूट चुके हैं। रात के अंधेरे में यह अवरोधक दिखाई नहीं देते और यहीं कारण है कि कई बाइक व कार सवार यहां 2 फीट नीचे गिर चुके हैं। खासकर पॉलिटेक्निक कॉलेज से शिवबाड़ी की

ओर का हिस्सा, जहां सड़क स्तर नीचे है, और महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज के हॉस्टल के पास से होते हुए वापस सार्दुल गंज सर्किल पर आकर समाप्त होता है। शिवबाड़ी रोड पर साइकिल ट्रैक के पास बने अवरोधक कई जगह से टूट चुके हैं। रात के अंधेरे में यह अवरोधक दिखाई नहीं देते और यहीं कारण है कि कई बाइक व कार सवार यहां 2 फीट नीचे गिर चुके हैं। खासकर पॉलिटेक्निक कॉलेज से शिवबाड़ी की

ओर का हिस्सा, जहां सड़क स्तर नीचे है, और महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज के हॉस्टल के पास से होते हुए वापस सार्दुल गंज सर्किल पर आकर समाप्त होता है। शिवबाड़ी रोड पर साइकिल ट्रैक के पास बने अवरोधक कई जगह से टूट चुके हैं। रात के अंधेरे में यह अवरोधक दिखाई नहीं देते और यहीं कारण है कि कई बाइक व कार सवार यहां 2 फीट नीचे गिर चुके हैं। खासकर पॉलिटेक्निक कॉलेज से शिवबाड़ी की

ओर का हिस्सा, जहां सड़क स्तर नीचे है, और महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज के हॉस्टल के पास से होते हुए वापस सार्दुल गंज सर्किल पर आकर समाप्त होता है। शिवबाड़ी रोड पर साइकिल ट्रैक के पास बने अवरोधक कई जगह से टूट चुके हैं। रात के अंधेरे में यह अवरोधक दिखाई नहीं देते और यहीं कारण है कि कई बाइक व कार सवार यहां 2 फीट नीचे गिर चुके हैं। खासकर पॉलिटेक्निक कॉलेज से शिवबाड़ी की

ओर का हिस्सा, जहां सड़क स्तर नीचे है, और महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज के हॉस्टल के पास से होते हुए वापस सार्दुल गंज सर्किल पर आकर समाप्त होता है। शिवबाड़ी रोड पर साइकिल ट्रैक के पास बने अवरोधक कई जगह से टूट चुके हैं। रात के अंधेरे में यह अवरोधक दिखाई नहीं देते और यहीं कारण है कि कई बाइक व कार सवार यहां 2 फीट नीचे गिर चुके हैं। खासकर पॉलिटेक्निक कॉलेज से शिवबाड़ी की

ओर का हिस्सा, जहां सड़क स्तर नीचे है, और महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज के हॉस्टल के पास से होते हुए वापस सार्दुल गंज सर्किल पर आकर समाप्त होता है। शिवबाड़ी रोड पर साइकिल ट्रैक के पास बने अवरोधक कई जगह से टूट चुके हैं। रात के अंधेरे में यह अवरोधक दिखाई नहीं देते और यहीं कारण है कि कई बाइक व कार सवार यहां 2 फीट नीचे गिर चुके हैं। खासकर पॉलिटेक्निक कॉलेज से शिवबाड़ी की

बढ़ेगा। इस ट्रैक की चौड़ाई लगभग तीन मीटर है, लेकिन यह पूरी तरह उपयोग लायक नहीं है। ट्रैक के बीचों-बीच अभी तक विद्युत पोल खड़े हैं, जिनके हटाने के निर्देश पहले ही दिए जा चुके थे। डेयरी बूथ और अन्य अतिक्रमणों ने रास्ता और संकरा कर दिया है। कई जगहों पर आवाग पशु विचरण करते हैं, जिससे साइकिलस्टों को जान जोखिम में डालकर निकलना पड़ता है।

बीकानेर साइक्लिंग क्लब से जुड़े रोहित व्यास ने बताया, हमने कई बार प्रशासन से अप्रग्र किया कि ट्रैक की हालत सुधारी जाए। हाइवे पर, साइकिलिंग करना बेहद खतरनाक है, लेकिन अब यहीं एकमात्र विकल्प बचा है। इतना पैसा खर्च कर जो सुविधा दी गई, उसकी देखरेख न होने से खिलाड़ी हतोत्साहित हो रहे हैं। सबसे पहले, ट्रैक के बीचों-बीच खंभे

बढ़ेगा। इस ट्रैक की चौड़ाई लगभग तीन मीटर है, लेकिन यह पूरी तरह उपयोग लायक नहीं है। ट्रैक के बीचों-बीच अभी तक विद्युत पोल खड़े हैं, जिनके हटाने के निर्देश पहले ही दिए जा चुके थे। डेयरी बूथ और अन्य अतिक्रमणों ने रास्ता और संकरा कर दिया है। कई जगहों पर आवाग पशु विचरण करते हैं, जिससे साइकिलस्टों को जान जोखिम में डालकर निकलना पड़ता है।

बीकानेर साइक्लिंग क्लब से जुड़े रोहित व्यास ने बताया, हमने कई बार प्रशासन से अप्रग्र किया कि ट्रैक की हालत सुधारी जाए। हाइवे पर, साइकिलिंग करना बेहद खतरनाक है, लेकिन अब यहीं एकमात्र विकल्प बचा है। इतना पैसा खर्च कर जो सुविधा दी गई, उसकी देखरेख न होने से खिलाड़ी हतोत्साहित हो रहे हैं। सबसे पहले, ट्रैक के बीचों-बीच खंभे

बढ़ेगा। इस ट्रैक की चौड़ाई लगभग तीन मीटर है, लेकिन यह पूरी तरह उपयोग लायक नहीं है। ट्रैक के बीचों-बीच अभी तक विद्युत पोल खड़े हैं, जिनके हटाने के निर्देश पहले ही दिए जा चुके थे। डेयरी बूथ और अन्य अतिक्रमणों ने रास्ता और संकरा कर दिया है। कई जगहों पर आवाग पशु विचरण करते हैं, जिससे साइकिलस्टों को जान जोखिम में डालकर निकलना पड़ता है।

बीकानेर साइक्लिंग क्लब से जुड़े रोहित व्यास ने बताया, हमने कई बार प्रशासन से अप्रग्र किया कि ट्रैक की हालत सुधारी जाए। हाइवे पर, साइकिलिंग करना बेहद खतरनाक है, लेकिन अब यहीं एकमात्र विकल्प बचा है। इतना पैसा खर्च कर जो सुविधा दी गई, उसकी देखरेख न होने से खिलाड़ी हतोत्साहित हो रहे हैं। सबसे पहले, ट्रैक के बीचों-बीच खंभे

बंदूकों से लैस होकर वहां पहुंचे और करीब 20 पुरुष हिन्दू पर्यटकों को मार दिया। यह भी कहा जा रहा है कि उन उग्रवादियों ने धर्म पूछकर पर्यटकों गोलियां मारी। संभव है कि उन व्यक्तियों के साथ में मौजूद स्त्रियों की मांगों में सिंदूर देखकर भी पुरुषों को मारा हो। उस दिन उस हत्याकांड के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में ढिलाई या पुलिस और सुरक्षा बलों की अनुपस्थिति को 'दी हिंदू' के दिनांक 22.04.2025 के ई-संस्करण में रात 9.29 बजे अपडेट किये गये समाचार तथा अन्य समाचारों में अगले दिन दिये गये समाचारों के अनुसार, केलर हाईकोर्ट के तीन न्यायाधीश अपने परिवारों के साथ जम्मू-कश्मीर में अवकाश पर्यटन पर गये हुए थे तथा 21 अप्रैल को पहलगाम पहुंचे थे। लेकिन वे 22 अप्रैल को सुबह 9.30 बजे के लगभग पहलगाम से श्रीनगर के लिए निकल चुके थे। घटना के बाद समाचार मिलने पर न्यायिक जगत में चिंता फैल गयी। लेकिन वे न्यायाधीशगण और उनके परिवार सुरक्षित थे, न्यायिक क्षेत्रों में लोगों को सुकून देने वाली बात थी। आतंकवादियों के द्वारा किये गये उस हत्याकांड से पर्यटक हतप्रभ हो गये। कुछ स्थानीय मुसलमानों ने मृतकों और घायलों को लाने ले जाने में सहायता की। कई पर्यटकों को अपने घरों में शरण भी दी।

उस हादसे के बाद पर्यटकों की संख्या में कमी होना लाजमी था। लेकिन सरकारें खासतौर से केंद्र सरकार के लिए उस हत्याकांड की उचित प्रतिक्रिया देना आवश्यक था। प्रधानमंत्री अरब की यात्रा बीच में ही छोड़कर आये लेकिन नौकरशाहों के साथ बैठक की और अगले दिन बिहार में आम चुनाव पूर्व की एक जनसभा में भाषण देने चले गये। पछर दो बार सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने की। अन्ततः 7 मई, 2025 को सीमा पर पाकिस्तान में अवस्थित आतंकवादियों के केंद्रों पर ड्रोन से हमला किया। इस अभियान को ‘ऑपरेशन सिंदूर’ नाम दिया गया। हमले की क्या स्ट्रेटजी थी, क्या राजनीति थी, क्या लक्ष्य थे, वे अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाये। भारतीय विदेश

मंत्री एस. जयशंकर का एक गुप्तचुपा बयान जरूर सामने आया कि भारत आतंकी अड्डों पर ही हमला करेगा क्योंकि भारत की तरफ से ‘ओपरेशन सिंदूर’ कोई युद्ध की घोषणा नहीं थी। लेकिन, चौथे दिन शाम 5:30 में अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की घोषणा की। उसके काफी देर बाद भारत और पाकिस्तान के अधिकारियों ने युद्ध विराम की घोषणा की। लगता है ट्रंप ने अपने शब्द भारत और पाकिस्तान की सरकारों के प्रधानों के मुंह में डाले हो।

क्या, क्यूं, कैसे, सभी सेनाएं और भारत की जनता युद्ध-विराम की घोषणा से स्तंभित रह गये, लेकिन सरकार की न तो आलोचना कर सके और न ही सरकार से कुछ पूछ सके। उन चार दिनों के हवाई, मशीनी युद्ध से भारत ने और पाकिस्तान ने क्या खोया, क्या पाया, इसका आंकलन और मूल्यांकन इतिहास में बाद में होगा। फिलहाल अमरीका का प्रत्यक्ष दखल उसके व्यापारिक हितों को ही परिलाक्षित करता है-निश्चित ही हमारे सबसे बड़े पड़ौसी चीन की भूमिका से भी इंकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि युद्ध विराम के तत्काल बाद अमरीका ने चीन के साथ व्यापार युद्ध को धीमा करने का उद्देश्य से टैरिफ में कमी करने की पहल की है। इससे जुड़ा एक अन्य मसला भी हो सकता है और वह है बलुचिस्तान का। जैसा कि बलुचिस्तानलिबरेशनआर्मीकी अपेक्षा थी कि भारत पाकिस्तान का युद्ध तेज हो कर लंबा चलेगा तो बलुचिस्तान को आजाद किया जा सकेगा। लेकिन, अमरीका नहीं चाहता कि बलुचिस्तान में शान्ति हो, क्योंकि बलुचिस्तान में खनिज संपदा बहुतायत से है वह अमरीका को किसी भी हालत में नहीं मिल पायेगी, चीन अपनी कोरीडोर की योजना के तहत उसे हासिल करना चाहेगा पर वह उसे मिल नहीं पायेगी, अगर बलुचिस्तान अशांत बना रहता है। यह एक प्रकार से व्यापारिक शीत-युद्ध है। इस मामले को बलुचिस्तान ने उभार भी कर दिया है यह संदेश देकर कि भारत बलुचिस्तान को एक ‘निर्वासित सरकार’ की मान्यता दे, वैसे कि तिब्बत को ‘निर्वासित सरकार’ की

मान्यता दे रखी है। लेकिन भारत सरकार अभी ऐसा कदम नहीं उठा सकती। बलुचिस्तान अपनी मुक्ति कस मार्ग खुद तय करे या भारत को गणतान्त्रिक संघ बन जाने पर उस संघ का सदस्य बने। क्योंकि आज के युग में किसी भी देश की सीमाओं को अतिक्रमण करके उसे अपनी सीमाओं में मिलाना संभव नहीं है, इसके विपरीत देशों का विघटन होकर नये स्वतंत्र देश अवश्य बन सकते हैं।

कई लोगों का मानना है कि भारत की मिसाइलों ने पाकिस्तान के किराना हिल्लस स्थित परमाणु बमों के गोदाम के पास विस्फोट किया। परमाणु विकीरण और परमाणु बमों के नष्ट होने के खतरों को देखते हुए अमरीका ने युद्ध विराम की घोषणा की। लेकिन चाहे भारत और पाकिस्तान परमाणु शक्ति सम्पन्न हों, वे परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से पहले हजार बार सोचेंगे क्योंकि दोनों ही देशों में आबादी का घनत्व बहुत ज्यादा है और यह माना जा सकता है कि दोनों ही देशों में न तो नादिरशाह जैसा कूर कोई है जो दिल्ली जैसे शहर के लोगों की लाशों पर अट्टहास कर रहा हो, और न ही अमरीकी राष्ट्रपति हेनरी एस ट्रम्प जैसा मानवता का दुश्मन कोई है जो अपने ही लोगों को वर्षों तक कष्ट भोगने के लिए परमाणु बम गिरा दे। बेशक, भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों की सरकारों में उग्र धार्मिक राष्ट्रवादी बैठे हों, जो कि कूर भी है, निष्ठुर भी है और मानता के प्रति असंवेदनशील भी हैं, फिर भी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर पायेंगे। जैसे पूंजीवादी साम्राज्यवादी अमरीका और उसके कट्टर विरोधी कम्युनिस्ट सोवियत संघ परमाणु हथियारों से सम्पन्न होते हुए भी उनका इस्तेमाल करने से 50 सालों तक क्या अभी तक भी बचते रहे हैं। और कभी गरम कभी नरम जैसा शीत युद्ध चलाते रहे। भारत और पाकिस्तान की जनता की रागों में वही पांच नदियों और गंगा-यमुना जैसी दो नदियों के पानी से बना खून बह रहा है वे अपने आपके दुश्मन नहीं हो सकते, चाहे उनकी सरकारें कितनी भी लड़ाइयां लड़ते रहे।

—**रामनिवास बैरवा,**
पूर्व क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

बढ़ेगा। इस ट्रैक की चौड़ाई लगभग तीन मीटर है, लेकिन यह पूरी तरह उपयोग लायक नहीं है। ट्रैक के बीचों-बीच अभी तक विद्युत पोल खड़े हैं, जिनके हटाने के निर्देश पहले ही दिए जा चुके थे। डेयरी बूथ और अन्य अतिक्रमणों ने रास्ता और संकरा कर दिया है। कई जगहों पर आवाग पशु विचरण करते हैं, जिससे साइकिलस्टों को जान जोखिम में डालकर निकलना पड़ता है।

हटाने की कार्रवाई की जाए। डेयरी बूथ और अन्य अतिक्रमणों को हटाया जाए। टूटे हुए अवरोधकों को रिपेयर कर पुनः स्थापन किया जाए। रात के समय ट्रैक पर रफ्लेक्टिव लाइट्स व बोर्ड लगाए जाए। ट्रैक की नियमित मॉनिटरिंग हो और हर 6 महीने में निरीक्षण अनिवार्य किया जाए। स्थानीय स्पोर्ट्स क्लब के साथ समन्वय बनाकर साइकिलस्टों की जरूरतें समझी जायें। बीकानेर का अगर स्पोर्ट्स सिटी के रूप में पहचान दिलानी है तो ऐसी अघूरी और उपेक्षित योजनाओं पर पुनर्विचार जरूरी है। सिर्फ निर्माण कर देना पर्याप्त नहीं, उसकी देखरेख और रखरखाव भी, उतना ही जरूरी है। प्रशासन को जल्द से जल्द इस मुद्दे पर सक्रियता दिखानी चाहिए, ताकि एक करोड़ की यह परियोजना फिर से बीकानेर के साइकिलस्टों के लिए प्रेरणा बन सके।

